

प्रेषक,

डी०एस० गब्याल,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
पौड़ी गढवाल।

**राजस्व अनुभाग-2**

देहरादून: दिनांक: 22 जुलाई, 2016

**विषय:-** उरेड़ा के तहत सोलर पावर प्लांट लगाये जाने हेतु ग्राम सीकू पट्टी खातस्यूं तहसील एवं जनपद पौड़ी गढवाल में कुल 1.048 है० भूमि श्री कविन्द्र सिंह बिष्ट पुत्र श्री दिगम्बर सिंह बिष्ट, ग्राम सीकू जनपद पौड़ी गढवाल को सशुल्क पट्टे पर किस्तों पर आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं०-1620/8-एल०ए०सी०/2015-16 दि०-02.03.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, जनपद एवं तहसील पौड़ी गढवाल की पट्टी खातस्यूं के तिमलाण तोक (ओरखिन्यू) के ग्राम सीकू के नॉन जेड०ए० खतौनी खाता सं०-44 के खसरा सं०-1316 मध्ये रकबा 1.048 है० भूमि (भीटा) उत्तराखण्ड सरकार के नाम दर्ज भूमि को शासनादेश संख्या-258/16(1)/73-राजस्व-1 दिनांक-09.05.1984, यथासंशोधित शासनादेश संख्या-1695/97-1-1(60)/93-280-रा०-1 दिनांक-12.09.1997 तथा शासनादेश सं०-1115/XVIII(II)/2016-18(184)/2015 दिनांक-15.06.2016 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत वर्तमान बाजार दर के दो गुने के बराबर एकमुश्त नजराना तथा मालगुजारी के 20 गुने के बराबर की धनराशि वार्षिक किराया नियत कर निर्धारित किस्तों (जिसका निर्धारण जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा) पर श्री कविन्द्र सिंह बिष्ट पुत्र श्री दिगम्बर सिंह बिष्ट, ग्राम सीकू जनपद पौड़ी गढवाल को निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन पट्टे पर सशुल्क आवंटित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. प्रश्नगत नॉन जेड०ए० भूमि आवंटन के पूर्व जमींदारी विनाश एवं भू-सुधार अधिनियम की धारा-132 के समकक्ष सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
2. चूंकि जिलाधिकारी द्वारा संबंधित शासनादेश दि०-9.5.1984 के अधीन निर्धारित प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्राविधानों का अनुपालन अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।
3. प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की गयी है। इस संबंध में आवासीय प्रयोजन के उपयोग के लिए सम्बन्धित प्राधिकारी व सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जाना जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तांतरित करने का अधिकार पट्टेदार को नहीं होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
5. प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-150/1/85(24)-रा-6 दिनांक-09 अक्टूबर, 1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षों के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार 30-30 वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढ़ाने का अधिकार होगा, जो पूर्व लगान के 1-1/2 गुना से कम नहीं होगा।
6. प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को नहीं रह जायेगी तो भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।
7. यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा संस्था का विघटन हो जाता है तो भूमि/भवन सील सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।

8. इस संबंध में सिविल अपील संख्या-1132/2011 (एस0एल0पी0)/(सी) संख्या-3109/ 2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य तथा सिविल अपील सं0-436/2011/SLP(C) NO. 20203/2007 झारखण्ड राज्य व अन्य बनाम पाकुर जागरण मंच व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश दि0-जनवरी, 2011 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी। जिलाधिकारी इसे सुनिश्चित करेंगे।
10. भू-उपयोगिता व पट्टे में इंगित शर्तों के अनुपालन के सन्दर्भ में शासन/जिलाधिकारी/अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकता है।
11. आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तों बिन्दु संख्या-01 से 10 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

भवदीय,

(डी0एस0 गब्याल)  
सचिव।

पू0पू0सं0- 545 /XVIII(II)/2016-03(12)/2016 संमदिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. श्री कविन्द्र सिंह बिष्ट पुत्र श्री दिगम्बर सिंह बिष्ट, ग्राम सीकू, जनपद पौड़ी गढ़वाल।
- ✓ 5. निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड सचिवालय।
6. प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0पी0 जोशी)  
अपर सचिव।